States/UT	Total
Bihar	54.58
Gujarat	78.36
Haryana	24.78
Himachal Pradesh	19.58
Jammu & Kashmir	15.65
Karnataka	91.65
Kerala	12.79
Madhya Pradesh	201.42
Maharashtra	144.01
Manipur	14.38
Meghalaya	19.18
Nagaland	13.86
Orissa	63.84
Punjab	12.30
Rajasthan	199.34
Sikkim	2.81
Tamil Nadu	44.01
Tripura	9.73
Uttar Pradesh	80.61
West Bengal	25.36
UTs	36.04
TOTAL :	1295.74

N.B. The above estimate is not based on a State-by-State survey of all wastelands in the country.

Reduction in rural development plan outlay

1623. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Rural Development Plan Outlay may be pruned drastically" appeared in the Economic Times dated 1st July, 1992;

(b) whether it is a fact that poverty alleviation schemes are likely to be drastically pruned;

(c) what are the reduction or proposed reductions in this vital sector; and

(d) what steps are being taken to ensure that outlay for rural development is enhanced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) For the Eighth Five Year-Plan, the Plan outlay for the Ministry of Rural Development has been stepped up from about Rs. 10,000 crores in the Seventh Plan to Rs. 30,000 crores. The various schemes to be taken up during the Eighth Five-Year Plan are under formulation.

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को धनराशि का आवंटन

1624. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है एवं इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में बैंकों की भूमिका की समीक्षा की गई है ; और

(ग) गुजरात को पूर्ण राज सहायता उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी०पी०) के अन्तर्गत गुजरात को वर्ष 1991-92 में कुल 2132.11 लाख रुपए की निधियां (केंद्र/राज्य) आवंटित की गई थी इसके मुकाबले 2770.44 लाख रुपए खर्च किए गए थे ।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए ऋण वितरण में बैंकों की भूमिका की गुजरात सहित सभी राज्यों में केंद्रीय स्तर पर ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति, खेड स्तरीय परामर्शदात्री समिति तथा खंड स्तरीयबैंकर्स समिति द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है ।

(ग) वर्ष 1991-92 में गुजरात को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2395.59 लाख रुपए की राज सहायता (सब्सीडी) रिलीज की गई थी जो कि वास्तव में राज्य को आवंटित 2132.11 लाख रुपए की राशि से अधिक थी ।

गुजरात में स्वरोजगार कार्यक्रम

1625. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ गांवों को "स्वरोजगार कार्यक्रम" के अंतर्गत लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये गांव कौन-कौन से हैं तथा ये किन-किन जिलों में स्थित हैं ;

(ग) इन गांवों में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Mechanism to check-up the use of Funds of I.R.D.P. and J.R.Y.

1626. **SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN**: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the mechanism of Central Government to check-up whether the funds provided to the State Governments towards IRDP and J.R.Y.; schemes are utilised properly in consonance with the guidelines given by the Central Government to achieve the desired objects;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether there is deviation from the objectives of the scheme by the various State Governments in implementing it to provide gainful employment to the people living below poverty line; and